मात्रा लाख गांठों में

वर्ष	गुजरात परिसंघ	सी सी आई	निजी व्यापार	कुल
1990-91	0.40	0.1170	0.3209	0.8387
1991-92	—	—	—	—
1992-93	0.671	0.583	—	1.254
1993-94	—	0.0305	—	0.0305

(ख) तथा (ग) सरकार का प्रयास यार्न, फैब्रिक्स, मेड-अप्स तथा सिले सिलाए कपड़ों जैसी मूल्य वर्द्धित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने का रहा है। निर्यात योग्य फालतू कपास को रिलीज करते समय सरकार का उद्देश्य, घरेलू बाजार में कीमतों का स्थिरीकरण, कपास उपजकर्ताओं को लाभप्रद मूल्यों का प्रावधान तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की कपास के एक स्थायी आपूर्तिकर्ता के रूप में उपस्थिति बनाए रखना, रहा है। निर्यात कोटाओं के आबंटिती अर्थात सी सी आई, राज्य तथा निजी व्यापारी उन्हें आबंटित मात्राओं को निर्यात करने के लिए बाजार खोज रहे हैं।

Liquidation of Unviable Textile Units in Gujarat

6570. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether NRF Empowered Committee handling VRS and redeployment scheme have committed the amount of Rs. 168 crores to be released to Gujarat for dismantling 14 unviable textile units under liquidations and for payment of statutory dues to pay 40,000 jobless workers and subsequently reimburse VRS fund spent on statutory dues to the workers by selling land, assets, etc. of unviable textile units;

(b) what are the major points in the proposal submitted by TLA to the NRF Empowered Committee with reliquidation of 14 closed textile mills;

(c) whether this matter is pending before government for long; and

(d) if so, by when the matter is likely to be disposed of?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कपास के मूल्य

6571. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत महीनों के दौरान देश में कपास के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह प्रतिबंध कुछ महीनों के पश्चात हटा लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो प्रतिबंध कौन से महीने में लगाया गया और कौन से महीने में हटाया गया; और

(घ) जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1994 के महीनों के दौरान कपास के मूल्य क्रमशः क्या-क्या थे?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) से (ग) कपास तथा सूती यार्न की कीमतों में आकस्मिक उछाल के परिणामस्वरूप सरकार ने 18-1-94 से अपरिष्कृत कपास के और आगे निर्यात को स्थगित कर दिया। सरकार ने अपरिष्कृत कपास के लदान न की गई मात्राओं, जोकि 9-2-94 से निर्यात के लिए संविदाकृत थीं, को आस्थगित कर दिया। तथापि संविदाकृत मात्राओं के निर्यात से प्रतिबंध 31-3-94 से उठा लिया गया।

(घ) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

कपास की महत्वपूर्ण किस्मों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, 1994 के महीनों के दौरान कपास की कीमतों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं

(प्रति कैंडी कीमत रु० में)

दिनांक	वी-797	जे-34	एस-6 (बी)	डीसीएच-32
15-1-94	11200	12300	16000	22000
15-2-94	11400	14900	16800	24000
15-3-94	14300	18000	19300	24500
15-4-94	15000	19300	21400	26000
30-4-94	14800	18500	21100	26000

गुजरात में जनता कपड़े का उत्पादन

6572. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरौला:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गुजरात में वर्ष 1991-92 में जनता कपड़े के उत्पादन हेतु निर्धारित किया गया लक्ष्य वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लक्ष्यों की तुलना में कम था;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षाकृत कम लक्ष्य निर्धारित किये जाने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1991-92 में उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हुआ था?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के दौरान जनता कपड़े को धीरे-धीरे समाप्त करने के भारत सरकार की नीति को मद्देनजर रखते हुए सभी राज्यों में जिसमें गुजरात भी शामिल है। वर्ष 1991-92 में उत्पादन लक्ष्यों में कमी की गई थी।

(ग) जी हां, वर्ष 1991-92 के दौरान जनता कपड़े के 13 मिलियन वर्ग मीटर के लक्ष्य में से 7.61 मिलियन वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया गया।

Cotton Export Policy

6573. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the cotton export policy has been formulated by Government under pressure from the powerful textile and handloom lobbies;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) The Government has a long-term cotton export policy which stipulates that five lakh bales of cotton would be exported at the beginning of the cotton season and subsequent releases would be made thereafter keeping in view the domestic availability and prices. The three main objectives of the cotton export policy are: (a) Stabilisation of cotton prices which is important for both the growers as well as the industry (b) ensuring remunerative prices to the cotton growers and (c) maintaining India's presence in the international markets as a stable supplier of cotton. While releasing quotas for exports, the Government tries to strike a balance· between the interests of the cotton growers on the one hand and that of the handloom weavers and the textile industry on the other.

Notification of Cotton Yarn Prices

6574. SHRI PRAGADA KOTAIAH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state whether there have been representations to the Ministry to notify the cotton yarn prices as required under the Essential Commodities Act, as there has been unusual, unprecedented hike in the price of yarn during the last six months, causing untold misery to millions of handloom weavers; and to arrange its procurement at stabilised prices and its